

खेल की आड में घर उजाड़ने के खिलाफ

बस्ती बचाओं अभियान 2010

c / o - 125 पॉकेट -4, बिंदापुर , नई दिल्ली -59 मोबाईल - 09211661830, 09289058222

खेल एक बहाना है, लाखों लाख कमाना है

खेल के पीछे खेल, जनता का तेल है

उन्होंने सबसे पहले मेडिकल के विस्तार के नाम पर झुग्गियों उजाड़ी, लोगों की मेडिकल का विस्तार जरूरी है, फिर उन्होंने स्कूल के विस्तार के नाम पर झुग्गियों उजाड़ी, लोगों को लगा की स्कूल के लिये झुग्गियों हटाई जा सकती है, लोग खामोश रहे, फिर उन्होंने हैजा और आंत्रशोध को खतम करने नाम पर झुग्गियों उजाड़ी, लोगों को लगा हैजा और आंत्रशोध झुग्गियों से होते हैं। फिर उन्होंने सड़क चौड़ी करने के नाम पर झुग्गियां उजाड़ी, रेहड़ी-पटरी हटाई, लोगों को लगा कि चौड़ी सड़क जरूरी है. फिर उन्होंने मेट्रो के लिये घर उजाड़े, तब घर वालों को लगा यह गलत है. आज वह खेल के नाम पर 44 झुग्गी बस्तियों को उजाड़ने पर आमादा है लेकिन शहर खामोश है.

मित्रो, दिल्ली सरकार के लिये यह साल इस मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष कोमन वेल्थ खेल कराने है जिसमे पूरी दुनिया के (इनकी तरह के दिमागी गुलामी करने वाले) लोग भाग लेंगे. इन खेलों कि तैयारी में वे पिछले कई सालों से सब काम भुलाकर जुटी पड़ी है. इसकी तैयारी में बहुत सी झुग्गी बस्तियों को हटाया गया, कुछ को वैकल्पिक स्थान भी मिले एवं बहुत से बेघर होकर हर रोज पुलिस के डंडे से परेशान हो रहे है.

जैसे जैसे खेल (अक्तूबर महिना) नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरकार नाकाम और खूंखार होती जा रही है और वह गुस्सा गरीबों पर निकल रही. सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली कि 44 झुग्गी बस्तियों को हटा कर राजीव रत्न आवास योजना के तहत उन्हें पुनर्वासित किया जाये जहाँ एक तरफ सरकार पुनर्वास कि बात कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकार के पास राजीव रत्न आवास योजना के तहत बवान, भुसगढ़, नरेला, घोगा और बपरोला में जो आवास बन रहे है उनकी संख्या 7900 है. इसमें एक मजेदार मोड़ यह है कि पुट्रुर्द, कंझावला, समसापुर, जोनपुर, नगली, सिरसपुर, रोहणी, द्वारका और सवदा घेवरा में इस योजना के तहत जो मकान बनने है, उसमें वर्षों लगेंगे. क्या सरकार का यह इरादा है कि कोमन वेल्थ के बहाने लोगों को दिल्ली से उजाड़कर बिना वैकल्पिक स्थान दिय सड़कों पर छोड़ देना चाहती है या फिर उन्हें खदेड़ कर शहर से बाहर भगाना चाहती है? अगर सरकार लोगों को उसकी झुग्गियों से उजाड़ कर सड़कों पर लाना चाहती है तो फिर शहर और सरकार दोनों को इस बात के लिये भी तैयार रहना चाहिए कि इन 44 बस्तियों को उजाड़ने से लगभग 25000 परिवार बेघर होंगे एवं 40000 बच्चों का स्कूल भी छूटेगा.

सरकार को शायद यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोग गाँव से शहर रोजगार कि तलाश में आ रहे हैं न कि शहर से दूर किसी ऊँचे घोंसले में बंद होने. बच्चों कि मुद्दे पर सरकार शैतान जैसी भूमिका अदा कर रही है. जहा एक तरफ सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाने का नाटक कर बिल पास करती है वही दूसरी ओर घर उजाड़ कर बेघर करने का एंव स्कूल से दूर करने की पूरी तैयारी भी करती है. जहा तक मजदूरों का प्रश्न है इन 44 बस्तियों में लगभग 30 से 35 हजार कामकाजी लोग रहते होंगे जो शहर को सुचारु रूप से चलाने में भूमिका निभा रहे है. हजारों बच्चों को स्कूल से दूर करना एंव हजारों को रोजगार से वंचित करना क्या सरकार की मंशा है?

आज सरकार कॉमनवेलथ खेल के किये शहर को सजाने नाम पर झुग्गियों को खत्म करना चाहती है. अगर हम इस मैके पर 1982 में आयोजित एशियाड की बात करें तो सरकार ने एशियाड की तैयारी के लिये पुरे देश में मजदूरों को बुलाया था ताकि वह दिल्ली में आकर निर्माण कार्यों में सरकार की मदद करें. खेल के खत्म होने के बाद सरकार उनके आवास का फिली में ही कोई प्रबंध हनी कर पाई. आज जिन मजदूरों को 44 बस्तियों को कॉमनवेलथ गेम के लिये सज रहे शहर की खूबसूरती के नाम पर उजाड़ा जा रहा है इनमे एक बड़ा हिस्सा उन मजदूरों का है जिनके बाप दादा एशियाड की तैयारी में दीली में निर्माण कार्य करने आए थे.

इस आदेश की दूसरी बड़ी परेशानी यह है की जिन लोगों को सरकार यह फ्लैट आवंटित करेगी उनसे 60000 रुपये भी लेगी जो झुग्गी वालों के लिये दे पाना बहुत मुशिकल होगा. दरसल यह गरीबों के नाम पर कम कीमत पर आवास प्राप्त करने का सरकार एंव उससे मिले बिचैलिओं का साधन है. राजीव रत्न आवास योजना गरीबों के लिये बनी है. लेकिन वह गरीब जो सचमुच रोज कमाते एंव रोज खाते हैं उनकी तो आमदनी भी इतनी नहीं है की वह पेट भर कर खाना खा सकें तो वह 60000 रुपये घर खरीदने के लिये कहाँ से लाएंगे? लोग फिर इन फ्लैटों के पेपर प्रोपर्टी डीलरों के हाथों बेच देने पर मजबूर होंगे और सरकार की भी यही इच्छा है.

ऐसा भी सुनने में आया है की दिल्ली सरकार की ओर से एक टीम मुंबई की मल्टी स्टोरी पुनर्वासि स्कीम को समझने गयी थी ताकि उसे दिल्ली में लागू कर सके. मुंबई की इस स्कीम को नाकामियों की लम्बी सूचि है लेकिन उनमें सबसे बड़ी विडम्बना यह है की मल्टी स्टोरी पुनर्वासि में पानी, बिजली, सुरक्षा, लिफ्ट सफाई आदि पर मासिक खर्च इतना अधिक है की गरीब बस्तियों में रहने वालों की आमदनी ही उतनी नहीं है कि वो चूका सके. साथ ही साथ इन मजदूरों का बड़ा तबका ऐसा भी जो निर्माण मजदूर या रेहड़ी-पटरी का काम करते हैं उनके लिये सीढ़ी, ठेला या भारी सामान लेकर तीसरी – चौथी मंजिल पर रहा नहीं जा सकता. इस हालत में लोग अपने रोजगार को ध्यान में रखते हुए ऐसे मकानों में नहीं रहना ही बेहतर समझते हैं और मकान बेचकर चले जाते हैं. ऐसा ही मुंबई में हुआ और सायद दिल्ली सरकार भी यही देखाना चाह रही है. जिन कम आमदनी वाले परिवार के लिया 800 से 9000 रुपये प्रतिमाह रख रखाव पर खर्च करना मुशिकल था उन्होंने या तो मकानों को बेच दिया या फिर किराये पर लगाकर खुद कहीं और रहने चले गए. मुमकिन है कि दुनारा वो फिर कहीं झोपड़ी ही डालें जहाँ रख रखाव खर्च उनकी आमदनी के अनुसार हो. बार बार पुनर्वासि के बावजूद शहर से झुग्गी बस्ती के खतम न होने का एक बड़ा कारण यही है कि मुंबई में रख रखाव आमदनी से अधिक है और दिल्ली में रोजगार से बहुत दूर पुनर्वासि.

कोमन वेलथ खेल – जैसा कि हम जानते हैं कि कोमन वेलथ खेल में वह लोग (देश) आते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जो लोग अंग्रेजों के गुलाम होने का जश्न मना सकते हैं इसका साफ़ मतलब है कि इनको या तो गुलामी ही पसंद थी या फिर इस खेल में वो अपना हित देख रहे हैं. दरअसल, ऐसे लोग (सरकार) हर ज़माने में रहे हैं जो अपना हित साधने में लगे रहे. आज खेल एक बहाना है, अगर देश में सचमुच खेल को बढ़ावा देना मकसद होता तो सरकार खेल के लिये तरह तरह कि योजनायें बनती. यहाँ तो खेल के नाम पर सरकार अपने ठेकेदारों एवं कम्पनियों कि चंडी कर रही है जिस काम का बजट 90000 करोड़ रुपये थे, आज कम समय के नाम पर वह बढ़कर न जाने कितना पहुँच गया है. अगर हम शहर के बाकि नुकाषणों कि कीमत लगाने लगे तो गिनती को शर्म आ जाएगी.

सरकार का एक ऐसा आयोजन जिससे न तो खेल का भला होने वाला है न ही आम नागरिकों का, बल्कि यह एक साजिश है जिस पर नहीं संसद में चर्चा कि गयी है. जरूरत इस बात कि है कि इस खेल पर हो रहे बनियावादी खर्च का विरोध करने कि जरूरत है साथ ही साथ खेल के बहाने मजदूरों को शहर से बाहर करने कि इस साजिश को नाकाम करने कि आवश्यकता है.

44 बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ
बस्ती बचाओ अधिवेशन

19 जून 2010 गाँधी शांति प्रतिष्ठान सुबह 10 से 5 बजे तक.

आप तमाम झुग्गी बस्ती में रहने वालों, झुग्गी बस्ती व शहरी गरीबों एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मुद्दों पर काम करने वाले साथी संघठनों से अपील है कि इस अधिवेशन में तन मन और धन से हिस्सा लें.